जुड़िए हमसे... पर @risingindore.news 0731-4032200

राइजिंग इन्दौर

सच का सारथी

इंदौर, बुधवार, 26 मार्च 2025

वर्ष -12, अंक-13

मूल्य 2 रूपए, पेज- 8

Inside page 06

76.5 करोड़ की रीवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना मंजूर...

1.9 किलोमीटर क्षेत्र में करेंगे काम, प्राधिकरण के बजट में किया जाएगा प्रावधान

राइजिंग इन्दौर
■ डॉ. जितेंद्र जाखेटिया

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने 76.5 करोड़ रुपए का रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1.9 किलोमीटर क्षेत्र में नाले के रूप में मौजूद नदी के किनारे के क्षेत्र को सजाने संवारने का काम किया जाएगा। इस काम के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के आगामी वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जाएगा।

कलेक्टर के द्वारा यह फैसला गत दिनों सिटी बस कंपनी के कार्यालय के सभागार में आयोजित किए गए प्रेजेंटेशन के दौरान लिया गया। इस प्रेजेंटेशन में इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा तथा इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार भी मौजूद थे। पूर्व में ही कलेक्टर के द्वारा इंदौर में कान्ह और सरस्वती नदी के किनारे के क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाने का काम प्राधिकरण को सौंपा गया था। इस काम में अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए यह समीक्षा बैठक रखी गई थी।

इस बैठक में बताया गया कि इंदौर में यह दोनों नदी की लंबाई 19.3 किलोमीटर है। अभी इसमें से 1.9 किलोमीटर क्षेत्र में नाले के रूप में बहने वाली इस नदी के किनारे के क्षेत्र के

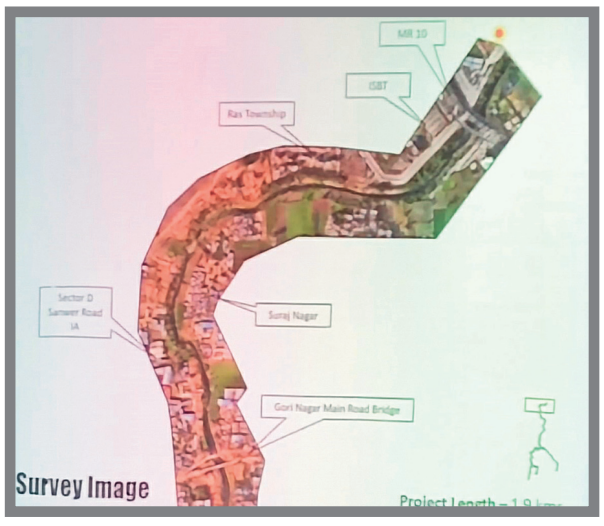

विकास की विस्तृत योजना तैयार हो गई है। इस योजना का प्रदर्शन इस बैठक में किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन पर 76.5 करोड रुपए का खर्च होना अनुमानित है। इस योजना के प्रदर्शन को देखकर कलेक्टर के द्वारा इस योजना को मंजूरी दे दी गई।

उन्होंने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि अगले वित्त वर्ष के लिए तैयार किए जाने वाले बजट में इस योजना को शामिल करते हुए इसके लिए समुचित राशि का प्रावधान किया जाए।

इस योजना को मंजूरी दिए जाने के पूर्व प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया कि ग्राम कुमेडी में प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए आईएसबीटी से लेकर गौरी नगर तक के क्षेत्र में इस योजना के तहत विकास किया जाएगा। यह पूरा क्षेत्र 1.9 किलोमीटर की लंबाई का है। इस क्षेत्र में नाले के पास के स्थान की चौड़ाई 20 मीटर रखी जाएगी। इसके बाद में 2.4 मीटर का फुटपाथ बनाया जाएगा। इसके बाद में 12.5 मीटर का हरियाली वाला क्षेत्र बनाया जाएगा जिसमें की प्लांटेशन किया जाएगा। इस तरह से नदी के दोनों तरफ 35-35 मीटर का विकसित क्षेत्र तैयार होगा। इस पूरे क्षेत्र में पाथ वे भी बनाया जाएगा। नागरिकों के बैठने के लिए कुर्सी भी लगाई जाएगी। इस क्षेत्र को बेहतर क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि इस तरह के विकास का मतलब तब ही है जब यह स्थान नाला ना होकर नदी के रूप में रहे। यदि इसमें पानी साफ होगा तो ही ऐसे विकास के बाद वहां पर नागरिकों की आवाजाही हो सकेगी। ध्यान रहे की इंदौर नगर निगम की स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा 3 किलोमीटर के क्षेत्र में नदी के किनारे के स्थान का विकास किया जा रहा है। इसमें से काफी क्षेत्र का विकास हो चुका है। इस स्मार्ट सिटी कंपनी के हवाले कृष्णपुरा पुल से लेकर अहिल्या आश्रम तक का क्षेत्र सौंपा गया है।

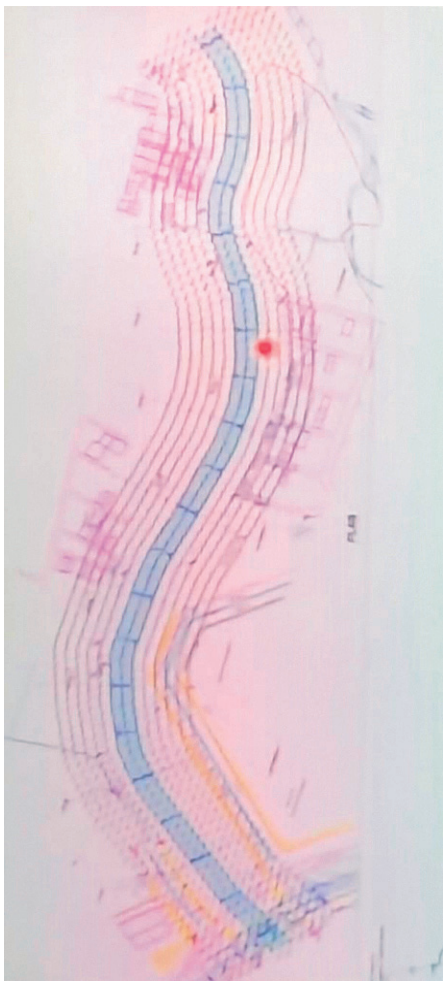

आउटफॉल्स का सर्वे फिर से करें

इस बैठक में कलेक्टर के द्वारा इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि कान्ह और सरस्वती में मिल रहे सीवरेज के आउटपाल का सर्व नए सिरे से किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें यह आईडेंटिफाई करना है कि किस-किस स्थान पर ड्रेनेज का पानी आकर मिल रहा है जिसके कारण यह नदी, नाले का रूप लेते जा रही है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को कहा कि एक बार फिर तेजी के साथ नया सर्वे कराया जाए।

राइजिंग इंदौर अब risingindore.com और MAGZTER.com पर डिजिटल रूप में भी उपलब्ध...

एम आर 12 की राह 1000 पट्टे वाले मकानों ने रोकी

अब जब मकान की व्यवस्था होगी तब हटाएंगे कब्जे, फिर बनेगी सड़क

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा 200 करोड रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क एम आर 12 की राह 1000 पट्टे वाले मकानों ने रोक दी है। अब इन मकानों को हटाकर इनमें रहने वाले परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा तब जाकर इस सड़क का निर्माण हो सकेगा।

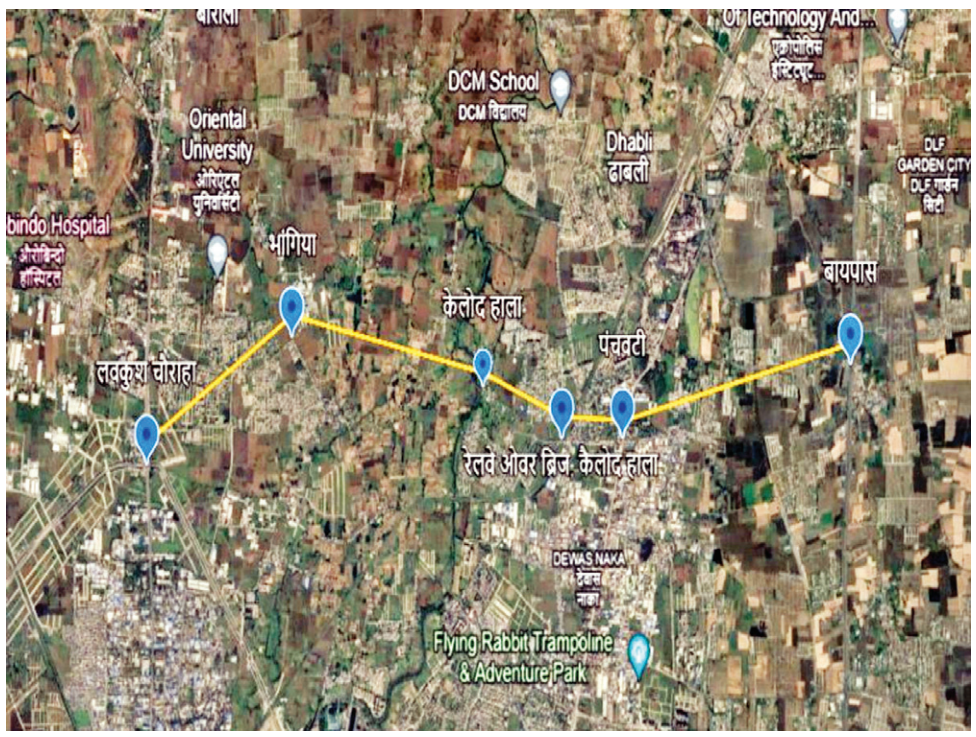

इंदौर के मास्टर प्लान में प्रावधान की गई यह सड़क बाईपास को सीधे उज्जैन रोड से जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क का निर्माण हो जाने से बाईपास से उज्जैन की तरफ जाने वाले यातायात का दूसरी सड़कों पर दबाव समाप्त हो जाएगा। इस सड़क के इस महत्व को देखते हुए ही प्राधिकरण के द्वारा इसके निर्माण के कार्य को हाथ में लिया गया है। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क में जिस स्थान पर बाधा नहीं है उस स्थान पर तो प्राधिकरण के द्वारा सड़क का निर्माण कर लिया गया है। इसके साथ ही करीब 35 ईंट भट्टे भी आपसे बातचीत के माध्यम से हटाकर उनसे भी सड़क के लिए जमीन ले ली गई है।

इस जमीन पर भी सड़क का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। यह सड़क प्रमुख रूप से दो हिस्से में है। पहला हिस्सा बाईपास से एबी रोड तक का है तो दूसरा हिस्सा एबी रोड से उज्जैन रोड तक का है। यह सड़क ग्राम अरंडिया से लव कुश चौराहा और फिर वहां से अरविंदो अस्पताल के आगे जाकर निकलती है। इस सड़क के माध्यम से उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के पर्व पर यातायात को आसानी से संभाला जा सकेगा।

अब इस सड़क की राह में एक बड़ी मुश्किल रविदास नगर और अन्य बस्ती की है। इन बस्ती में 1000 मकान बने हुए हैं। इन सभी मकान को हटाना है तब जाकर सड़क बन सकेगी। यह मकान सरकार के द्वारा अपनी योजना के तहत दिए गए पट्टे की जमीन पर बनाए गए हैं। ऐसे में इन मकानों को ना तो अवैध निर्माण कहा जा सकता है और ना ही अतिक्रमण। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि इन मकानों में रहने वाले परिवारों का व्यवस्थापन किया जाए। इस बारे में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि इस स्थान पर कुल 1000 मकान बने हुए हैं। हमें आगे की सड़क का निर्माण करने के लिए इन मकानों को हटाना पड़ेगा। इन मकान में रहने वाले लोगों के लिए 1000 मकान की व्यवस्था करने की चुनौती है। अभी नगर निगम के पास भी इतनी बड़ी संख्या में मकान तैयार नहीं है जहां पर की इन मकान में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा सके। ऐसे में अब प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत गरीबों के लिए आवास बनाना चाहता है। प्राधिकरण की इच्छा है कि वह आवास बनाकर उन आवास में ही इन नागरिकों को शिफ्ट कर दें।

इस मामले में समस्या यह है कि यह पूरी योजना बहुत बड़ी और बहुत लंबी है जिसमें की बहुत ज्यादा समय लगना है। यदि इस योजना के आधार पर इन मकानों को हटाने का काम रोका गया तो यह सड़क बहुत ज्यादा विलंब का शिकार हो जाएगी।

बोरिंग का पानी परीक्षण के बगैर पीने के लिए सप्लाई कर दिया

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 14 चयनित निकायों में से 11 निकायों द्वारा 1,204 बोरवेलों से जलापूर्ति के लिए जल परीक्षण न कराने का खुलासा हुआ है।

भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि मध्य प्रदेश के 14 चयनित निकायों में से 11 निकायों के 1,204 बोरवेलों से जलापूर्ति के पहले जल परीक्षण नहीं किया गया। इनमें से किसी भी बोरवेल का नियमित जल परीक्षण नहीं कराया गया और सीधे जनता को जल मुहैया कराया गया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इन निकायों को यह भी नहीं पता था कि भूजल की गुणवत्ता कैसी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नगरीय निकायों द्वारा बोरवेल के पानी का इस्तेमाल कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन निकायों में बोरवेल की नियमित जल परीक्षण की अनदेखी की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक खतरनाक बीमारियों का सामना कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में अधिकांश लोगों को पानी की आपूर्ति हैंडपंप और बोरवेल के जरिए की जाती है, लेकिन इन पानी स्रोतों की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बोरवेल और हैंडपंपों की गहराई 300 फीट से अधिक होती है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट जैसे खतरनाक तत्व मौजूद होते हैं। इन खनिजों का उच्च स्तर मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है।

शिकायत मिलने पर करते हैं जांच

खंडवा नगर निगम ने कहा कि जब भी शिकायतें मिलती हैं, तब ही पानी की जांच कराई जाती है। वहीं, आष्टा, गंज बासौदा, लोहारदा, रतलाम और रामपुर नैकिन नगर निगमों ने माना कि उन्होंने कभी भी जल परीक्षण नहीं कराया। मंदसौर और नरसिंहगढ़ ने कहा कि परीक्षण कराए गए हैं, जबकि सतना नगर निगम ने सीएजी को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। महाराजपुर ने 12 और इछावर ने चार परीक्षण रिपोर्ट कैग को प्रस्तुत की थीं।

कैग की रिपोर्ट में यह सिफारिश

कैग ने नगरीय विकास और आवास विभाग को सिफारिश की है कि सभी निकायों में जल प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं और पानी का नियमित परीक्षण किया जाए। यदि पानी में कोई हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हें दूर करने के बाद ही पानी की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा, संयंत्रों और पाइपलाइनों की नियमित सफाई की भी सिफारिश की गई है।

खुले में रसायन का भंडारण

निकायों में चूने, फिटकिरी और ब्लीचिंग पाउडर का भंडारण खुले और नमी वाले स्थानों पर किया गया था, जो कि गलत है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आष्टा, गंजबासौदा, खंडवा, नरसिंहगढ़, रतलाम और सतना में ये रसायन खुले और नमी वाले स्थानों पर पड़े हुए थे। सतना नगर निगम ने इसे धुलाई के कारण नमी आने का कारण बताया, जबकि रतलाम और नरसिंहगढ़ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह पूरी स्थिति यह दर्शाती है कि निकायों की लापरवाही के कारण नागरिकों को सुरक्षित जल की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

नामांतरण और लीज रिन्यूअल के लिए नहीं काटने होंगे ida के चक्कर

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के तहत अब नागरिकों को नामांतरण और लीज नवीनीकरण जैसे सामान्य कामों के लिए प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। इन कामों को करवाने के लिए नागरिक ऑनलाइन ही अपना आवेदन कर सकेंगे। इस आवेदन का निपटारा भी ऑनलाइन के आवेदन के आधार पर ही होगा।

इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) में अब तक संपत्तिधारक को कोई भी काम कराने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आइडीए ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर दिया है। लीज रिन्यूअल, फ्री होल्ड और नामांतरण जैसे प्रकरणों के आवेदन पोर्टल से ही भरे जाएंगे। जो नहीं भर सकते हैं उनके लिए आइडीए में ही एक टेबल लगाई जाएगी।

धीरे-धीरे सरकारी महकमा डिजिटलाइजेशन पर जा रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी से बचाया जा सके और काम में पारदर्शिता भी रहे। इसके चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉलोनी सेल का काम भी ऑनलाइन कर दिया, जिसमें विकास अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस के आवेदन किए जा सकते हैं। फाइल कहां अटकी है और किसने अटका रखी है ये सबकुछ ऑनलाइन नजर आएगा।

खोला जाएगा सहायता केंद्र

आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया, सोमवार सुबह 10 बजे अध्यक्ष व संभागायुक्त दीपक सिंह की मौजूदगी में पोर्टल को शुरू किया जाएगा। 31 मार्च तक ट्रायल पर रहेगा, जिससे आने वाली समस्या को ठीक कर अप्रेल से लागू किया जाएगा। जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते है उनके लिए सहायता केंद्र बनाया जाएगा जिस पर कर्मचारी मौजूद रहेंगे। आने वालों के आवेदन खुद भरेंगे।

लंबित हैं दो हजार केस

पिछले दो साल में आइडीए ने मुहिम चलाकर लीज नवीनीकरण व फ्री हेल्ड के केस बड़ी संख्या में निपटाए गए। नामांतरण का आंकड़ा मिलाकर 38 हजार की संख्या हो गई है और सभी को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। अब दो हजार केस ही लंबित हैं। इसके बाद आईडीए पूरे दस्तावेजों को डिजिटलाइज्ड करने जा रहा है ताकि फाइल के घूमने और चोरी होने की घटनाएं खत्म हो जाएं। हालांकि, प्रारंभिक तौर पर फाइलों का कोडिंग कर दिया है। इससे पता चल जाता है कि वह किसके पास कब से है।

आवेदन के बाद फाइल खुद-ब-खुद आगे बढ़ेगी

आईडीए ने भी ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदक को वर्तमान में लीज रिन्यूअल, फ्री होल्ड और नामांतरण का आवेदन करने के लिए आइडीए आना पड़ता था। काम करने के लिए आठ से दस चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इस प्रक्रिया से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद फाइल खुद-ब-खुद आगे बढ़ेगी। इंजीनियर को समय सीमा में रिपोर्ट लगानी होगी तो संपदा अधिकारी को निराकरण करना होगा।

कलेक्टर की नई पहल, जनता से लेंगे तहसीलदारों के काम का फीडबैक

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सुशासन संवाद केन्द्र के माध्यम से अब तहसीलदारों के काम का भी फीडबैक लिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाना और आवेदकों से उनके अनुभव के आधार पर काम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। पटवारियों की शिकायतों के बाद अब तहसीलदारों के काम का वेरिफिकेशन भी आवेदकों के फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित समय सीमा में काम हुआ या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी, जिससे असंतुष्टि वाली शिकायतों के साथ फोर्स क्लोज की गई शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

उच्च अधिकारियों की भी होगी समीक्षा

इंदौर जिले में पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद अब कलेक्टर उच्च अधिकारियों को भी सुशासन संवाद केन्द्र के दायरे में लाकर उनकी कार्यशैली का मूल्यांकन करेंगे। इस केन्द्र के माध्यम से अब यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदकों की संतुष्टि के साथ-साथ निर्धारित समयसीमा में राजस्व प्रकरणों का सही तरीके से निपटारा किया गया है या नहीं। यदि काम की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो सम्बंधित तहसीलदारों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकरण निर्धारित समय में निपटाए जाएं और गुणवत्ता बनाए रखी जाए।

अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश : 31 मार्च तक पूरा किया जाए कार्य- कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों से उनके कार्यों की जांच की। उन्होंने पिछड़े तहसील के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 मार्च तक वसूली के साथ-साथ डायवर्सन नामांतरण, सीमांकन और बटांकन के सभी प्रकरण समयसीमा में पूरे किए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने आरआरसी के प्रकरणों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे काम में और तेजी आएगी।

सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ 30 दिन का शक्कर का उपवास

4 दिन में 63 लोग उपवास नहीं कर सके तो हो गए अभियान से बाहर

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

इंदौर। अपनी बेहतर फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर के समाज प्रेमी नीरज याग्निक ने सोशल मीडिया के माध्यम से 30 दिन का शक्कर उपवास का अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 2100 लोग शामिल हुए। शुरू के चार दिन में 63 लोग शक्कर का उपवास नहीं कर सके तो इस अभियान से बाहर हो गए।

याग्निक ने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए शक्कर का 30 दिन का उपवास का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि 30 दिन तक यदि हम शक्कर नहीं खाते हैं तो उसे हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रोग्राम इससे एक तरफ जहां हमारी शुगर कंट्रोल होती है तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सी बीमारियों के खतरे कम हो जाते हैं। इस अभियान को जब शुरू किया गया तब यह उम्मीद थी कि इस अभियान में काम से कम 1000 लोग जुड़ जाएंगे। फेसबुक पर पोस्ट डालकर शुरू किए गए इस अभियान में 2100 लोग जुड़ गए और इन लोगों के द्वारा एक महीने तक शक्कर किसी भी रूप में नहीं खाने का संकल्प लिया गया।

याग्निक ने बताया कि अभी तक इस अभियान में चार दिन हो चुके हैं लेकिन शक्कर खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण 63 लोग इस अभियान से जुड़ने के बाद बाहर हो गए हैं। शेष लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और 30 दिन तक शक्कर नहीं खाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से हार्ट अटैक सहित कई बीमारियों से शुगर के मरीज को बढ़ाने की पहल की जा रही है। इस समय देश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ाने वाली बीमारी डायबिटीज ही है। इस बीमारी के कारण बहुत सारी नई बीमारियां भी पैदा हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया का सहारा लेकर यह अभियान शुरू किया गया है।

संपादकीय...

विकास की दौड़ में आगे निकलने के लिए तैयार है प्राधिकरण

इंदौर शहर में विकास कार्य करने में इंदौर विकास प्राधिकरण बहुत आगे चल रहा है । पिछले वर्ष में 4 फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण कर उन पर यातायात शुरू कर दिया गया है। अब जल्द ही ग्राम कुमेडी के आईएसबीटी को शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही वृद्ध जनों के लिए बनाए गए केंद्र का भी लोकार्पण करने की तैयारी है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश

■ गौरव गुप्ता

अहिरवार के द्वारा जिस तरह से विकास कार्य करने में रुचि ली जा रही है उसे देखते हुए अब इंदौर के संभाग आयुक्त और कलेक्टर भी प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्य करवाने में रुचि ले रहे हैं। इस स्थिति के चलते हुए ही अब प्राधिकरण को नाला बन चुकी नदी के किनारे को सजाने का काम भी सौंपा जा रहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण विकास को लेकर नई योजनाएं भी तैयार कर रहा है।

दही खाने के कई फायदे हैं और गर्मी में दही को खट्टा होने से बचाना है

दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि दही खाने से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि

पाचन तंत्र बेहतर होता है- दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं।

इम्यूनिटी मजबूत होती है- दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

हड्डियां और दांत मज़बूत होते हैं- दही में कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस होता है, जो हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है।

डॉ. आरती मेहरा
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ
7999788456

त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद- दही में मौजूद विटामिन और मिनरल्स त्वचा और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं।

वज़न कम करने में मददगार- दही में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और यह लंबे समय तक भूख को नियंत्रित रखता है।

दिल स्वस्थ रहता है- दही में गुड फैट्स (अच्छे वसा) होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं।

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है- दही में पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

मुंह के छाले दूर होते हैं- दही खाने से मुंह के छाले दूर होते हैं।

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड एक एक्सफ़ोलिएटर के रूप में काम करता है, जो मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है।

गर्मी में जल्दी खट्टा क्यों हो जाता है दही

गर्मी के मौसम में दही जितनी आसानी से जमता है। यह उतनी ही तेजी से खट्टा भी हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज इसका सॉल्यूशन और दही जमाने का सही तरीका जानते हैं।

1. दही का जामन हमेशा गुनगुने दूध में डालना चाहिए।
2. दही जमाने के लिए उसे ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां वो हिल न सके। अगर बर्तन हिल गया तो समझ लें वो सही तरह से जमेगा नहीं।

उसे जमने के लिए गर्माहट की जरूरत होती है। अगर आपने उसे सही तरह से ढंककर किसी गर्म जगह पर नहीं रखा, तब भी अच्छे से नहीं जमेगा।

अगर बहुत गर्म दूध में जामन डालकर ढंक दिया है तो पानी-पानी हो जाएगा।

3. दूध को दही में बदलने वाले लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया को गर्माहट की जरूरत होती है।

गर्मी में तापमान ज्यादा होता है। यह बैक्टीरिया को तेजी से गुणा यानी मल्टिप्लाई करने में मदद करता है। इस वजह से दूध तेजी से दही में बदलने लगता है।

सर्दी में टेम्परेचर गर्म नहीं होने की वजह से इसके अनुकूल नहीं होता। इसलिए कुछ लोग सर्दी के दिनों में दही जमाने के बाद उस पर गर्म कपड़ा रखते हैं।

4. गर्मी में दही खट्टा होने की वजह क्या है? आमतौर से ये तीन-चार वजहें हैं। जैसे-

गर्म दूध में जामन डालकर गर्म जगह पर रखना।

खट्टा जामन से दही जमाना।

दही जमने के बाद बहुत देर तक गर्मी में बाहर छोड़ देना।

5. गर्मी में रात में दही जमाना सही है या दिन में? गर्मी के दिन में अगर दही जमाने के लिए रखेंगे तो जमने के बाद पानी छोड़ देगा। इससे वो गाढ़ा नहीं हो पाएगा। इसे शाम के 4-5 बजे जमाएंगे तो 6 घंटे में यह जम जाएगा।

दही जब जम जाए तो उसे आप तुरंत इस्तेमाल न करें। फ्रिज में रख दें। सुबह आपको एकदम गाढ़ा और मीठा दही खाने को मिलेगा।

अगर घर पर जामन नहीं तब भी दही जम सकता है क्या? बिल्कुल। इसके लिए दूध को हल्का

गुनगुना करना होगा। इसके बाद कुकिंग एक्सपर्ट डॉक्टर आरती मेहरा की दी गई 4 ट्रिक्स में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं-

हरी मिर्च- दूध को एक कटोरी में निकाल लें, अब इसमें दो हरी मिर्च डाल दें। मिर्च में डंठल होना जरूरी है। मिर्च पूरी तरह इसमें डूब जाना चाहिए। इसके बाद दूध को ढककर 6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। दही जम जाएगा।

नींबू- इसके लिए आपको गुनगुने दूध में दो चम्मच नींबू रस डालना है। इसके बाद दूध को ढककर 6-7 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दें। दही जम जाएगा।

चांदी का सिक्का- इसके लिए गुनगुने दूध में चांदी का सिक्का या अंगूठी को दूध में डालकर 8 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखना होगा।

लाल मिर्च- हरी मिर्च की तरह लाल मिर्च से भी ऐसा ही दही जमेगा। इसके लिए सूखी लाल मिर्च को 7-8 घंटे के लिए गुनगुने दूध में डुबोकर किसी गर्म जगह रख दें। दही जम जाए

मोटर दुर्घटना मुआवजे की राशि सीधे दावेदारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सड़क दुर्घटना मुआवजा सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। इससे पीड़ितों को जल्द राहत मिलेगी। बीमा कंपनियां अब डिजिटल तरीके से भुगतान करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि पीड़ितों के बैंक खाते की जानकारी लें... और अवार्ड में ही बैंक खाते का उल्लेख करें ताकि बीमा कंपनियां सीधे दावेदार के बैंक खाते में अवार्ड राशि जमा कर सके।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगी बड़ी राहत

सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने से पीड़ितों को मिलेगा जल्द मुआवजा

सीधे बैंक अकाउंट में आएगी सड़क हादसे के मुआवजे की राशि

हर साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं में करीब पांच लाख लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं। इन हादसों के बाद मुआवजे के लिए बड़ी संख्या में दावे मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में दायर किए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा है कि मुआवजे की राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए, ताकि उन्हें जल्द राहत मिल सके और देरी न हो। आमतौर पर, बीमा कंपनियां मुआवजे की राशि पहले ट्रिब्यूनल में जमा करती हैं, जिससे पीड़ितों तक पैसा पहुंचने में काफी समय लग जाता है। कई बार पीड़ितों को यह जानकारी भी नहीं होती कि उनके लिए कोई मुआवजा राशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में जमा हुई है। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल ट्रांसफर का तरीका अपनाने का निर्देश दिया है। एक मामले में हाईकोर्ट ने 12 लाख रुपये मुआवजा तय किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 36.8 लाख रुपये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को यह निर्देश दिया जा सकता है कि मुआवजे की राशि सीधे दावेदार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए और इसकी जानकारी ट्रिब्यूनल को दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) को चाहिए कि वह शुरुआत में ही पीड़ितों से उनके बैंक खाते की जानकारी ले। इससे बीमा कंपनियां बिना किसी देरी के सीधे उनके खाते में मुआवजा जमा कर सकेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ट्रिब्यूनल अंतिम फैसला सुना दे, तो बीमा कंपनियां तुरंत डिजिटल पेमेंट (DBT) के जरिए पैसा ट्रांसफर करें।

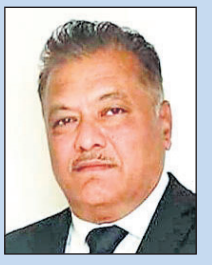

संजय मेहरा
हाईकोर्ट एडवोकेट
98270 74132

पिछले पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल हजारों लोगों की जान जाती है और लाखों लोग घायल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए दिया है-

2018- 1.5 लाख मौतें, 4.6 लाख घायल
2019- 1.5 लाख मौतें, 4.4 लाख घायल
2020- 1.3 लाख मौतें, 3.4 लाख घायल
2021- 1.5 लाख मौतें, 3.8 लाख घायल
2022- 1.6 लाख मौतें, 4.4 लाख घायल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब समय आ गया है कि ट्रिब्यूनल और बीमा कंपनियां भी इसी प्रणाली को अपनाएं, ताकि पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े। इस निर्णय के बाद दुर्घटना पीड़ितों को जल्द और आसानी से मुआवजा मिल सकेगा। अब ट्रिब्यूनल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सड़क सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे लोगों में यह विश्वास बढ़ेगा कि अगर किसी हादसे में वे पीड़ित होते हैं, तो उन्हें जल्द न्याय मिलेगा और उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने परमिंदर सिंह बनाम हनी गोयल और अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।

इस निर्णय में निर्देश दिया गया है कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे की राशि सीधे दावेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी और नौकरशाही अड़चनें समाप्त की जा सकें।

यह मामला 3 जून 2014 की एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें परमिंदर सिंह, जो उस समय 21 वर्षीय पशु चिकित्सा के छात्र और राज्य स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, एक कार (PB-03-X-0169) की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के परिणामस्वरूप वह 100 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हो गए और उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT), बठिंडा से मुआवजे की मांग की।

MACT ने उन्हें 5,16,000 का मुआवजा दिया, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर रु. 15,25,600 कर दिया। इस मुआवजे से असंतुष्ट होकर, परमिंदर सिंह ने और अधिक मुआवजे की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामले में कानूनी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित कानूनी प्रश्न थे- आय का आकलन और भविष्य की कमाई की हानि - क्या उच्च न्यायालय ने परमिंदर सिंह की संभावित कमाई का गलत आकलन किया था? भविष्य की संभावनाओं का अधिकार- क्या एक छात्र होने के बावजूद सिंह को भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजा मिलना चाहिए? विकलांगता, चिकित्सा खर्च और दर्द एवं पीड़ा के लिए पर्याप्त मुआवजा - क्या पहले दिए गए मुआवजे में सिंह की दीर्घकालिक चिकित्सा और व्यक्तिगत देखभाल की जरूरतों को ध्यान में रखा गया था? मुआवजे के भुगतान का तरीका - मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुचारू करने की आवश्यकता।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों द्वारा दिया गया मुआवजा अपर्याप्त था और निम्नलिखित सुधार किए- आय का पुनर्मूल्यांकन, उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई रु. 5,600 प्रति माह की आय को रु. 7,500 कर दिया गया, यह देखते हुए कि सिंह एक पशु चिकित्सा छात्र और राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे। भविष्य की संभावनाएं- 40 प्रतिशत वृद्धि के साथ सिंह की संभावित मासिक आय को रु. 10,500 निर्धारित किया गया।

मोटर दुर्घटना मामलों में सीधे बैंक खाते में मुआवजा ट्रांसफर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में सभी मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे की राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में जमा करने का निर्देश दिया।

कोर्ट की टिप्पणी आज के डिजिटल युग में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑनलाइन बैंकिंग ने वित्तीय लेन-देन को सरल बना दिया है। अदालत में मुआवजा जमा करने से अनावश्यक देरी और वित्तीय नुकसान होता है। इसलिए, बीमा कंपनियों को अब सीधे दावेदारों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि ट्रांसफर करनी होगी।

तेजी से भुगतान – अदालतों में धनराशि जमा करने और निकासी के लिए अतिरिक्त आवेदन की जरूरत नहीं होगी।

वित्तीय नुकसान से बचाव

वकीलों और दलालों के माध्यम से कटौती को रोका जा सकेगा

लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा - मुआवजा सीधे पीड़ितों के खाते में पहुंचने से किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस प्रणाली को परिवार कानूनों के तहत दिए जाने वाले भरण-पोषण और भूमि अधिग्रहण मुआवजे जैसी अन्य वित्तीय मामलों में भी लागू किया जाए।

भोपाल के जीआईएस पर 82 करोड़ खर्च

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

राजधानी भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) पर 82.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) पर 82.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे के सवाल के जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए आयोजित विभिन्न सम्मेलनों पर कुल 268 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस बार GIS और रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव्स, इंटरएक्टिव सेशंस आदि के जरिए कुल 30177 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय संग्राहलय में किया गया था। यहां पर एक दर्जन से ज्यादा डोम लगाए गए थे। मेहमानों को कार्यक्रम स्थल तक लाने ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें और गोल्फ कार किराए से ली गई थी। मेहमानों के लिए समिट में खास और विशेष इंतजाम किए गए थे। इस पर जीआईएस से पहले रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया। निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यूके-जर्मनी और जापान की यात्रा पर गए।

साज सज्जा पर करोड़ों खर्च

ग्लोबल इंवेसटर्स समिट (जीआईएस) के आयोजन से पहले भोपाल शहर की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसमें लोक निर्माण विभाग में सड़क, नगर निगम ने पेटिंग और साज सज्जा के अलावा अन्य एजेंसियों ने भोपाल की सजावट पर राशि खर्च की। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया गया।

उज्जैन में जाने वाले यात्रियों से यूजर्स चार्ज लेने का प्रस्ताव

इन यात्रियों को पार्किंग और शौचालय की सुविधा देंगे मुफ्त

बाबा महाकाल की नगरी में बनाए गए महाकाल लोक को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव बनाया गया कि आप उज्जैन में जाने वाले यात्रियों से यूजर्स चार्ज वसूल किया जाए। इन यात्रियों को पार्किंग और शौचालय की सुविधा मुफ्त दी जाए।

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

उज्जैन नगर निगम अब उज्जैन में आने वाले यात्रियों से यूजर्स चार्ज वसूल करने की तैयारी कर रहा है। इन यात्रियों से प्रवेश मार्ग पर ही एक निश्चित राशि यूजर्स चार्ज के रूप में ले ली जाए। इसके साथ ही इन यात्रियों को उज्जैन यात्रा के दौरान पार्किंग और शौचालय की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। इस तरह का सुझाव नागरिकों की ओर से आने के बाद उज्जैन नगर निगम के द्वारा महापौर परिषद की बैठक में बजट में ही सुझाव को शामिल करने के बारे में विचार किया गया। नगर निगम की आय बढ़ाने के बारे में नागरिकों और पार्षदों की ओर से बहुत से सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझाव पर विचार किया गया। इसी में यूजर्स चार्ज का भी सुझाव था इस सुझाव में कहा गया कि राजस्थान के ऋषभदेव में आने वाले यात्रियों को प्रवेश मार्ग पर ही शुल्क देना होता है। वहां पर यात्रियों से शहर में आने के बाद पार्किंग और अन्य सुविधा का शुल्क नहीं लिया जाता है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शहर के सभी प्रवेश मार्ग पर नगर निगम के द्वारा चौकी बनाकर यूजर्स चार्ज वसूलने पर विचार किया जा रहा है। महापौर परिषद के सदस्यों का मानना है कि किस तरीके को अपनाने से निगम की आय में इजाफा होगा।

1 अप्रैल से बंद होगी शराब दुकानें

राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में यह फैसला लिया गया है कि उज्जैन सहित 19 शहरों में शराब की दुकान नए वित्त वर्ष से बंद कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के परिणाम स्वरुप उज्जैन शहर में शराब की 17 दुकान बंद होगी। काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में शराब की दो दुकानों का संचालन किया जाएगा। ताकि इन दुकानों से श्रद्धालु शराब खरीद कर काल भैरव मंदिर में चढा सकें। इसके साथ ही 1 अप्रैल से किसी भी होटल और बार में शराब नहीं बेची जा सकेगी। किसी भी घर में भी शराब की चार बोतल रखने पर भी प्रतिबंध होगा।

इस सप्ताह आपके सितारे

26 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025

किसी के यहां होंगे शुभ कार्य तो किसी के कारोबार में होगी वृद्धि

मेष - इस सप्ताह भूमि अथवा वाहन संबंधी कोई कार्य होगा। स्वयं का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति का विपरीत व्यवहार पीड़ित कर सकता है। संतान से भी कुछ कष्ट संभव है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में धनात्मकता रहेगी।

वृषभ - कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। आवक अच्छी होगी। व्यय भी अधिक होंगे। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख उत्तम है। कोई यात्रा संभव है। घर में किसी शुभ कार्य होने की रूपरेखा बनेगी। जीवनसाथी के व्यवहार से संतोष रहेगा।

मिथुन - इस सप्ताह प्रेम संबंधों की प्रति सावधान रहें। जीवनसाथी से कष्ट संभव है। कारोबार ठीक ठीक रहेगा। आवक मध्यम, व्यय अधिक। संतान पक्ष ठीक रहेगा। इस सप्ताह बेवजह के विवादों से बचें। पिता को आंशिक कष्ट हो सकता है। रुका हुआ कुछ पैसा मिलेगा।

कर्क - इस सप्ताह किसी से बेवजह का विवाद हो सकता है। सावधान रहें। कारोबार अच्छा चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि संभव है। किसी कार्य के होने से संतोष मिलेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य एवं व्यवहार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। वाहन में टूट फूट संभव है।

सिंह - इस सप्ताह मानसिक तनाव कम होंगे। बहुप्रतीक्षित कोई कार्य होगा। मित्र सहयोग करेंगे। जीवनसाथी का स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। प्रेम संबंध ठीक ठीक रहेंगे। वाहन में टूट-फूट संभव है। संतान पक्ष कुछ पीड़ित करेगी। विद्यार्थीगण परेशान रहेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी।

कन्या - शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह ठीक नहीं। कारोबार में विघ्न आएंगे। संतान पक्ष ठीक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग और व्यवहार आपको मानसिक सुकून देने वाला होगा। शत्रु सिर उठा सकते हैं। लाभ सीमित होंगे।

तुला - शारीरिक स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा। संतान पक्ष पीड़ित करेगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और व्यवहार ठीक-ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। शत्रु परास्त होंगे। मित्र सहयोग करेंगे। किसी शुभ कार्य होने की संभावना है। किसी से बेवजह विवाद न करें। भूमि, वाहन से कष्ट।

वृश्चिक - इस सप्ताह मानसिक परेशानी ज्यादा रहेगी। किसी का विपरीत व्यवहार कष्ट देगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध फले फूलेंगे। संतान पीड़ित करेगी। लाभ में कमी आएगी। कारोबार मध्यम रहेगा। वाहन सावधानी से चलावें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु - इस सप्ताह प्रेम संबंधों के प्रति बहुत अधिक सावधान रहें अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहेगा। वाहन से कष्ट होगा। विवादों से बचें। कारोबार अच्छा रहेगा। शत्रु दबेंगे। स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यय अधिक होंगे।

मकर - किसी व्यक्ति के धनात्मक व्यवहार से आपको खुशी मिलेगी घर में अमूमन शांति एवं प्रफुल्लता रहेगी। कारोबार अच्छा चलेगा। आवक भी अच्छी होगी किंतु बेवजह कुछ नुकसान संभव है। वाहन सुख श्रेष्ठ है। संतान पक्ष से कुछ कष्ट संभव है। विवादों से बचें।

कुंभ - इस सप्ताह संतान संबंधी कोई कार्यज होगा। व्यय अधिक होगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह श्रेष्ठ है। मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। भूमि संबंधी कोई कार्य होगा। वाहन सुख उत्तम। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनात्मकता रहेगी।

मीन - इस सप्ताह किसी कार्य की कोई योजना फलीभूत होती दिखाई देगी। प्रेम संबंध खूब फले-फूलेंगे। संतान पक्ष अल्प कष्ट देगा। दूरस्थ यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से धनात्मकता रहेगी। बेवजह के विवादों को टालें। आवक अच्छी होगी किंतु व्यय अधिक होंगे।

श्रीमान उमेश पांडे
ज्योतिष एवं वास्तुविद
महात्मा गांधी मार्ग, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
मो. 8602912030

इस सप्ताह की ग्रह स्थितियां

■ **सूर्य** - कुंभ में 15 से मीन में ■ **चंद्र** - सिंह से तुला तक
■ **मंगल** - मिथुन ■ **बुध** - मीन ■ **गुरु** - वृषभ ■ **शुक्र** - मीन
■ **शनि** - कुंभ ■ **राहु** - मीन ■ **केतु** - कन्या

परिसीमन के खिलाफ दक्षिण भारत के राज्य हुए लामबंद

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन करने की पहल की गई है। इस पहल के पीछे भाजपा की इच्छा उत्तर भारत के राज्यों में सीटों को बढ़ाने की है। इसके परिणाम स्वरुप दक्षिण भारत का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में परिसीमन के खिलाफ दक्षिण भारत के राज्य लामबंद हो गए हैं।

परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्यों की मीटिंग के बहाने स्टालिन गैर बीजेपी शासित राज्यों की गोलबंदी कर रहे हैं और परिसीमन से होने वाले कथित नुकसान की ओर जनता का ध्यान खींचना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि स्टालिन ने इस मुद्दे को इस समय उठाया है जब तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं।

परिसीमन की पिच पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सियासी बैटिंग करने को तैयार हैं। देश की राजनीति में तमिल प्रतिनिधित्व के सवाल को आधारकर DMK नेता स्टालिन दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गोलबंदी तो कर रहे हैं। वे देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के उन राज्यों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहे हैं जिन्होंने परिसीमन से कथित रूप से अपनी लोकसभा सीटें कम होने का अंदेशा जताया है।

तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम व क्षत्रप दलों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आह्वान पर निष्पक्ष परिसीमन की मांग को बलवती करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इस परिसीमन का आधार मौजूदा आबादी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे मौजूदा जनसंख्या से जोड़कर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब तक परिसीमन को लेकर बयानबाजी हो रही थी। ऐसे में स्टालिन की अगुवाई में निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक शनिवार को चेन्नई में हुई। जेएसी की अगली बैठक हैदराबाद में होगी।

तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा

बैठक में केरल के सीएम पिनराई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के अलावा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, क्षेत्रीय कांग्रेस, वामदलों व अन्य क्षत्रप दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में अज्ञात कारणों से तृणमूल कांग्रेस और आंध्रप्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने इसी मौके पर इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

राज्यों से परामर्श करें व आबादी का आधार बने 1971

लगभग तीन घंटे तक चली वार्ता के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिसकी जानकारी द्रमुक लोकसभा सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत जेएसी ने जोर दिया कि विभिन्न हितधारक राज्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना परिसीमन अभ्यास शुरू नहीं किया जाए। प्रस्ताव की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

- परिसीमन अभ्यास में पारदर्शिता हो, ताकि सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, सरकारों और अन्य हितधारकों को इसमें विचार-विमर्श, चर्चा और योगदान करने का अवसर मिल सके।
- 42वें, 84वें और 87वें संविधान संशोधनों की मंशा के तहत आबादी नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने वाले राज्यों के हितों की रक्षा की जाए और 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो तथा इसे अगले 25 वर्षों तक स्थाई कर दिया जाए।
- जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- बैठक में प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के सांसदों की कोर कमेटी बनेगी जो आगे की रणनीति तय करेगी और इसी सत्र में प्रतिवेदन के साथ पीएम से मिलेगी।
- बैठक वाले दल अपने राज्यों की विधानसभा में निष्पक्ष परिसीमन को लेकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजेंगे।
- जेएसी समन्वित जनमत जुटाने की रणनीति के माध्यम से अपने-अपने राज्यों में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी।

शाह के आश्वासन पर संदेह

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन को अस्पष्ट बताते हुए संदेह जताया है। शाह ने कहा था कि आगामी परिसीमन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। स्टालिन ने चेतावनी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसे हश्र से बचने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बैठक में वे बोले कि प्रस्तावित परिसीमन से तमिलनाडु को कम से कम आठ सीटों का नुकसान होगा। मणिपुर दो साल से जल रहा है और इसके लोगों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि उनके पास अपनी आवाज उठाने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

WhatsApp पर आने वाला है गजब फीचर, AI लिखेगा यूजर्स के लिए मैसेज

WhatsApp दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर Meta AI का फीचर मिलता है। WhatsApp पर जल्द ही दूसरे AI फीचर्स भी आने वाले हैं।

रिपोर्ट्स की मानें, तो इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म AI पावर्ड रि-राइट फीचर पर काम कर रही है। रि-राइट फीचर की मदद से यूजर्स अपने मैसेज को अलग-अलग स्टाइल में लिख सकते हैं। ये फीचर यूजर्स के मैसेज को प्रूफरीड भी कर सकेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म Meta AI के लिए टू-वे लाइव वॉयस चैट फीचर पर काम कर रहे ही।

एंड्रॉयड वर्जन पर किया गया है स्पॉट

एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp टेक्स्ट रि-राइटिंग फीचर पर काम कर रहा है, जो AI पर बेस्ड होगा। इस फीचर के बारे में एंड्रॉयड ऐप्लिकेशन पैकेज यानी APK से जानकारी मिलेगी। इस फीचर को Android version 2.25.8.5 पर स्पॉट किया गया है।

हालांकि, ये फीचर विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। AI रि-राइट फीचर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन के रूप में उपलब्ध होगा। ये बटन पेंसिल आइकॉन रूप में होगी, जो सेंड बटन के ऊपर दिखेगा। ये बटन सिर्फ तभी दिखेगा, जब यूजर कुछ टाइप करेगा।

कैसे काम करेगा ये फीचर?

कुछ वर्ड्स को टाइप करने के बाद यूजर्स को इस पेंसिल आइकॉन पर टैप करना होगा। यहां टैप करते ही यूजर्स को टेक्स्ट एडिटर का एक्सेस मिलेगा। इसकी मदद से यूजर्स तमाम टेक्स्ट रि-राइटिंग ऑप्शन का फीचर मिलेगा। इसकी मदद से यूजर्स अपने मैसेज को फनी, रिफ्रेज, सपोर्टी और दूसरे तरीकों से बदल सकते हैं। हालांकि, वॉट्सऐप का ये फीचर कब तक लॉन्च होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर यूजर को Meta AI का फीचर मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं। ये AI बॉट आपके लिए फोटोज क्रिएट कर सकता है। कंपनी इसे और बेहतर बनाने पर काम कर रही है।

यातायात सुधारने की सारी मुहिम हो गई फुस्स

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

कलेक्टर आशीष सिंह से लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव तक सभी ने इंदौर के यातायात को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। इस कार्य को करने के लिए सभी ने अपनी योजना बनाई और अपनी योजना के अनुसार काम भी किया। इसमें से किसी का भी काम लक्ष्य के अनुसार परिणाम नहीं दे सका है। यही कारण है कि संजय सेतु से लेकर राजमोहल्ला चौराहे तक जवाहर मार्ग पर और गोराकुंड चौराहा से लेकर किशनपुरा तक एमजी रोड पर सुबह से लेकर शाम तक जाम ही लगा रहता है। इस क्षेत्र से वाहन चालकों के लिए अपना वाहन लेकर निकलना मुश्किल हो गया है। एमजी रोड और जवाहर मार्ग को वनवे के रूप में परिवर्तित करने का फैसला कागज पर ही सिमट कर रह गया है। इस फैसले पर क्रियान्वयन करने की सारी कोशिश अब तक नाकाम रही है। इस फैसले पर क्रियान्वयन नहीं होने के कारण इन दोनों सड़कों पर यातायात की स्थिति बदहाल है। अब तो ऐसा लगता है जैसे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यातायात सुधारने की दिशा में काम करना ही बंद कर दिया है। कलेक्टर भी जब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसे समय पर यातायात सुधार को लेकर गंभीर हो जाते हैं और फिर बाद में पूरा मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है।

गाइडलाइन से 96 गांव की जमीनों के भाव में आया जोरदार उछाल

दावे आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव इंदौर से भोपाल भेजा

राइजिंग इन्दौर
■ रिपोर्टर

1 अप्रैल से नई वित्त वर्ष में लागू होने वाली जमीन की कीमत को प्रदर्शित करने वाली सरकारी गाइडलाइन के कारण 96 गांव की जमीनों के भाव में जोरदार उछाल आ गया है। इस गाइडलाइन पर प्राप्त हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए भोपाल भेज दिया गया है।

इंदौर शहर में अहिल्या पथ, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस्टर्न व वेस्टर्न बायपास और इंदौर-उज्जैन ग्रीन फीडर एक्सप्रेस जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में आने वाली जमीनों की सरकारी कीमतें आसमान पर पहुंचने वाली हैं। पहली बार योजना लागू होने के बाद योजनाओं की जमीनों की गाइड लाइन बढ़ाई जा रही है। इन योजनाओं के 96 गांवों में 46 से 274 फीसदी की वृद्धि हो रही है। इसके साथ इंदौर जिले में अब संपत्ति की लोकेशन 4996 हो गई हैं।

नई गाइड लाइन का रास्ता साफ

मध्यप्रदेश को रजिस्ट्री से सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इंदौर में अप्रेल से नई गाइड लाइन लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। रजिस्ट्रार विभाग ने एआई के माध्यम से अधिक मूल्य पर होने वाली लोकेशनों की फेहरिस्त बनाई और 3226 लोकेशनों पर गाइड लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। जिला मूल्यांकन समिति में उसे रखा गया, जिस पर 138 दावे-आपत्तियां आई थीं। सभी का निराकरण कर दिया गया है। वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू ने बताया कि 2024-25 में जिले में 4686 लोकेशन थीं, जिसमें 240 नई लोकेशन जोड़ी गईं।

70 नई लोकेशन जोड़ने के आवेदन

प्रस्तावित गाइड लाइन पर दावे-आपत्तियां बुलाई गईं तो 70 नई लोकेशन जोड़ने के आवेदन आए। इन्हें मिलाकर 4996 लोकेशन हो गई हैं। 3226 पर वृद्धि प्रस्ताव के साथ 5 लोकेशन और जोड़ दी हैं। इससे 3231 लोकेशन पर वृद्धि की जा रही है। औसत 25.95 फीसदी की वृद्धि है, जिसमें अधिकतम 274 तो न्यूनतम 10 प्रतिशत है। प्रस्तावित गाइड लाइन पर आए दावे-आपत्तियां का निराकरण कर जिला मूल्यांकन समिति ने गेंद केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पाले में डाल दी है।

किसानों की बल्ले-बल्ले

जमीन की सरकारी कीमतों में बढ़ोतरी से योजना में आने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है। अहिल्या पथ के गांवों में 67 से 189 तो इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के गांवों में 93 से 233 फीसदी की वृद्धि देखी गई। इंदौर-उज्जैन ग्रीन फीडर एक्सप्रेस के गांवों में 40 से 200 प्रतिशत, ईस्टर्न बायपास के गांवों में 46 से 275 प्रतिशत और वेस्टर्न बायपास में 100 से 200 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

प्रकाशक एवं मुद्रक गौरव गुप्ता द्वारा स्वामी अशर्फीलाल विमलादेवी मीडिया सर्विसेस प्रा.लि. के लिए डी. बी. कॉर्प लि., 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, सांवेर रोड इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 401-402, डी.एम. टॉवर जंजीरवाला चौराहा, इंदौर 452001 से प्रकाशित। संपादक- दीपक गुप्ता, कार्यकारी संपादक-जितेंद्र जाखेटिया*। फोन नंबर-0731-4032200, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2013/52898* समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार।